भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं0 63

06 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

iz/kkuea=h vkokl ;kstuk ds varxZr lLrs vkokl

***63- Jh pUnz izdk'k pkSèkjh%**
Jh dq:ok xksjkaryk ekèko%

D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ izèkku ea=h vkokl ;kstuk ¼ih,e,okbZ½ ds fofHkUu pj.kksa ds rgr lLrs vkoklksa ds fuekZ.k ds fy;s p;fur fd;s x;s 'kgjksa dh >kj[kaM vkSj vka/kz izns'k lfgr jkT;&okj la[;k fdruh gS(

¼[k½ D;k mDr ;kstuk ds igys pj.k esa lfEefyr fd;s tkus okys 100 'kgjksa dk p;u djus dk y{; gkfly dj fy;k x;k gS(

¼x½ ;fn gka] rks igys pj.k esa blds varxZr fufeZr fd;s x;s vFkok fd;s tk jgs fo'ks"kdj >kj[kaM esa fufeZr fd;s x;s vFkok fd;s tk jgs ?kjksa dh la[;k fdruh gS(

¼?k½ D;k ljdkj ?kjksa ds fuekZ.k ds lacaèk esa fof'k"V xq.koÙkk ekun.Mksa dk ikyu djrh gS(vkSj

¼³½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k g® vkSj bl lacaèk esa D;k mipkjkRed mik; fd;s x;s gS\

<u>उत्तर</u>

<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)</u>

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

****

<u>**विवरण**</u>

"पीएमएवाई के अंतर्गत किफायती आवास" के संबंध में दिनांक 06.02.2020 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं0 *63 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

*****

(क): प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) मिशन के तहत किफायती आवासों के निर्माण के लिए चयनित शहरों की संख्या का झारखंड और आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है ।

(ख): जी हां । अधिसूचित आयोजना/विकास क्षेत्रों सहित जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और तत्पश्चात् अधिसूचित कस्बों को शामिल करने के लिए मार्च, 2016 में पीएमएवाई-यू मिशन के तहत शहरों को शामिल किए जाने के फेज़-वार प्रावधान में छूट दी गई थी । अब तक, पीएमएवाई-यू मिशन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत देश के 4,521 शहरों में 1.12 करोड़ आवासों की वैध मांग की तुलना में 1.03 करोड़ आवास संस्वीकृत किए जा चुके हैं ।

(ग): अब तक, पीएमएवाई-यू मिशन के तहत झारखंड राज्य में 1,98,751 आवास संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से क्रमश: 1,35,156 आवास निर्माणाधीन हैं और 76,865 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/सौंपे जा चुके हैं । झारखंड राज्य में पीएमएवाई-यू मिशन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा अनुलग्नक-II पर दिया गया है ।

(घ) और (ड.): जी हां । पीएमएवाई-यू मिशन के दिशानिर्देशों में यह दिया गया है कि मिशन के प्रत्येक घटक के तहत आवासों का निर्माण राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी) में दिए गए मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए । मिशन के अंतर्गत आवासों को इस प्रकार डिज़ाइन और निर्मित किया गया है कि वे भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन इत्यादि के विरूद्ध संरचनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करें और एनबीसी व अन्य संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों के अनुसार हों । मिशन के अंतर्गत संस्वीकृत आवासों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा नियमित गुणवत्ता जांच के अतिरिक्त सभी चालू परियोजनाओं पर तृतीय पक्षीय गुणवत्ता निगरानी (टीपीक्यूएम) रखी जानी भी अनिवार्य है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मिशन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत निर्माण की गुणवत्ता

सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्षीय गुणवत्ता निगरानी एजेंसी (टीपीक्यूएमए) को नियुक्त करते हैं।

दिनांक 06.02.2020 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं0. *63 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू मिशन के अंतर्गत किफायती आवासों के निर्माण के लिए चयनित शहरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं0.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	शहरों/कस्बों में संस्वीकृत आवास (सं.)	संस्वीकृत आवासों की सं0 (सं.)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	1	612
2	आंध्र प्रदेश	183	20,07,430
3	अरूणाचल प्रदेश	29	7,230
4	असम	98	1,17,493
5	बिहार	145	3,13,039
6	चंडीगढ़ (यूटी)	1	436
7	छत्तीसगढ़	165	2,55,011
8	दादरा और नगर हवेली (यूटी)	1	4,333
9	दमन और दीव (यूटी)	2	1,236
10	दिल्ली (यूटी)	5	17,303
11	गोवा	14	855
12	गुजरात	192	6,44,446
13	हरियाणा	86	2,67,727
14	हिमाचल प्रदेश	53	9,986
15	जम्मू और कश्मीर	80	54,615
16	झारखंड	45	1,98,751
17	कर्नाटक	277	6,52,455
18	केरल	96	1,29,555
19	लद्दाख (यूटी)	2	1,777
20	लक्षद्वीप (यूटी)	-	0
21	मध्य प्रदेश	385	7,84,976
22	महाराष्ट्र	386	11,77,084
23	मणिपुर	27	42,825
24	मेघालय	10	4,692
25	मिज़ोरम	23	30,357
26	नागालैंड	32	32,001
27	ओडिशा	118	1,54,073

28	पुडुचेरी (यूटी)	6	13,419
29	पंजाब	167	90,631
30	राजस्थान	171	2,00,530
31	सिक्किम	8	537
32	तमिलनाडु	719	7,68,938
33	तेलंगाना	70	2,16,860
34	त्रिपुरा	20	82,088
35	उत्तर प्रदेश	678	15,74,070
36	उत्तराखंड	94	39,880
37	पश्चिम बंगाल	132	4,11,344
कुल*		**4,521**	**103,22,560**

* इसमें सीएलएसएस के अंतर्गत 13,965 आवास शामिल हैं, जिनके लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों को हाल-ही-में धनराशि जारी की गई है ।

दिनांक 06.02.2020 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं0. *63 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

झारखंड राज्य के लिए पीएमएवाई-यू मिशन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति

क्रम सं0	विवरण	पीएमएवाई-यू मिशन के अंतर्गत उपलब्धि
1	अनुमोदित परियोजना(परियोजनाओं) की संख्या	389
2	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रू. में)	12,382.67
3	संस्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)	2,994.53
4	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)	1,643.87
5	संस्वीकृत आवास (सं0.)	1,98,751
6	निर्माणाधीन आवास (सं0.)	1,35,156
7	निर्माण पूर्ण किए जा चुके आवास (सं0.)	76,865
8	कब्ज़ा किए जा चुके आवास (सं0.)	76,611

****